

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 1332
दिनांक 30.07.2024 को उत्तरार्थ

पंचायती राज के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण

- +1332. श्री बसवराज बोम्मई:
श्री पी. सी. मोहन:
डॉ. राजीव भारद्वाज:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री गणेश सिंह:
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
श्री अरविंद धर्मापुरी:
श्री मुरारी लाल मीना:
श्री विजय बघेल:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह:
श्री जुगल किशोर:
श्री खगेन मुर्मु:
डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:
सुश्री कंगना रनौत:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री अनिल फिरोजिया:
श्री करण भूषण सिंह:
श्री विजय कुमार दूबे:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पंचायती राज के प्रतिनिधियों को प्रबंधन नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और उनके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

- (ग) राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण और प्रशिक्षित पंचायती राज प्रतिनिधियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश में पंचायतों को वर्तमान में प्रदान की जा रही इंटरनेट और कम्प्यूटर जैसी अवसंरचना का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री (प्रो. एस पी.सिंह बघेल)

(क) जी हाँ, महोदय। केंद्रीय प्रायोजित योजना संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास करना है, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं के हितधारकों की निरंतर क्षमता निर्माण की गतिविधियाँ शामिल हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी और पीआर), राज्यों के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वर्ष भर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेतृत्व प्रशिक्षण की पहुंच को और बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में एक नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम तैयार किया है, जो एक रणनीतिक पहल है और इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत राज संस्थाओं के अधिकारियों की नेतृत्व क्षमताओं को मजबूत करना है।

(ख) मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम अहमदाबाद), भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर (आईआईएम अमृतसर), भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया (आईआईएम बोधगया), भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू (आईआईएम जम्मू), भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग (आईआईएम शिलांग), भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक (आईआईएम रोहतक), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद (आईआईटी धनबाद) और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद, गुजरात के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमताओं को उन्नत करना है, ताकि पंचायत शासन में प्रभावी तरीके से सुधार हो सके और जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार किया जा सके। जबकि कार्यक्रम राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर मॉड्यूल डिज़ाइन में लचीलापन प्रदान करता है, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम का मुख्य ध्यान नेतृत्व और टीम वर्क, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, रचनात्मकता और ग्रामीण नवाचार पर है।

(ग) पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम का परिचयात्मक कार्यक्रम 15-19 जनवरी 2024 के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा नेतृत्व और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। विभिन्न राज्यों, जिनमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं, से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(घ) पंचायत एक राज्य का विषय होने के नाते, पंचायतों के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करने, जिसमें कम्प्यूटर और इंटरनेट भी शामिल हैं, की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों पर होती है। हालांकि, पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत, मंत्रालय सीमित मात्रा में ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर प्रदान करके, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के

प्रयासों की सहायता करता है, तथा भारतनेट परियोजना के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी के समर्थन की सुविधा प्रदान करता है। योजना के तहत अनुमोदित कंप्यूटरों की राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार विवरण और भारतनेट परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध इंटरनेट कनेक्शनों की जानकारी **अनुबंध-II** में दी गई है।

अनुबंध -I

दिनांक 30/07/2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1332 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

15-19 जनवरी 2024 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में आयोजित प्रारंभिक नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित प्रतिभागी

क्रम सं.	राज्य	नाम	पदनाम
1	आंध्र प्रदेश	श्री मरदाना पोली नायडू	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़ेडपीपी, विशाखापत्तनम
2	छत्तीसगढ़	डॉ. रेनुका श्रीवास्तव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बलौद
3	छत्तीसगढ़	सुश्री नम्रता जैन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भटापारा
4	दादरा एवं नगर हवेली	श्री रामजी भीखा बमुनिया	अध्यक्ष, जिला पंचायत, दीव
5	गोवा	डॉ. अजय गौड़े	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रभार: सचिव पुनर्वास बोर्ड, गोवा
6	गोवा	सुश्री फ्लोरिना कोलास्को	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दक्षिण गोवा जिला पंचायत
7	गोवा	श्री सिद्धेश एस. नाइक	अध्यक्ष, उत्तर गोवा जिला पंचायत
8	गोवा	सुश्री वानिया वालनकानी बापटिस्टा	सदस्य (दक्षिण जिला पंचायत, गोवा)
9	गुजरात	श्री दिनेश रमेश गुरव	जिला विकास अधिकारी, अमरेली
10	गुजरात	श्री मनीष गुर्वानी	जिला विकास अधिकारी, वलसाड
11	हरियाणा	सुश्री सुमन खीचर	अध्यक्ष जिला परिषद, फतेहाबाद
12	हरियाणा	सुश्री वैषाली सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद महेन्द्रगढ़
13	हिमाचल प्रदेश	डॉ. नीला कुमारी	अध्यक्ष जिला परिषद चंबा
14	हिमाचल प्रदेश	श्री मनेश कुमार यादव	एडीसी, पीडी, डीआरडीए हमीरपुर
15	हिमाचल प्रदेश	श्री महेंद्र पाल गुर्जर	एडीसी/सीईओ, जिला परिषद उना
16	हिमाचल प्रदेश	श्री अजय कुमार यादव	एडीसी, सोलन
17	जम्मू एवं कश्मीर	सुश्री पूजा ठाकुर	अध्यक्ष, DDC, किश्तवाड़
18	जम्मू एवं कश्मीर	सुश्री ज्योति रानी स्लथिया	अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी DDC, रियासी
19	जम्मू एवं कश्मीर	श्री नासिर नजीर लोन	जिला विकास परिषद, कूपवाड़ा, सदस्य
20	जम्मू एवं कश्मीर	श्री नासिर अहमद लोन	अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी DDC, शोपियां

क्रम सं.	राज्य	नाम	पदनाम
21	कर्नाटका	सुश्री गरिमा पंवार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यदगिरी
22	लद्दाख	श्री पंचोक ताशी	कार्यकारी आयुक्त (RDD/PRI)
23	मध्य प्रदेश	सुश्री नेहा यादव	अध्यक्ष, जिला परिषद शिवपुरी
24	मध्य प्रदेश	सुश्री कामना सिंह	अध्यक्ष, जिला परिषद भिंड
25	महाराष्ट्र	सुश्री मीनल यू. करनवाल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नांदेड़
26	महाराष्ट्र	श्री पंकज खोमेश्वर रहांगडे	अध्यक्ष जिला परिषद, गोंडिया
27	ओडिशा	सुश्री सास्मिता मेलका	जिला परिषद अध्यक्ष, कोरापुट
28	ओडिशा	श्री लक्ष्मी नारायण सबर	PS अध्यक्ष, गजपति आर. उडयागिरी ब्लॉक
29	ओडिशा	श्री कौशिक कुमार प्रधान	जिला परिषद अध्यक्ष, देवगढ़
30	ओडिशा	श्री प्रकाश चंद्र प्रधान	PS अध्यक्ष, जगतसिंहपुर, बालिकुड़ा ब्लॉक
31	राजस्थान	श्री पारस राम मीना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चुरू
32	सिक्किम	श्री सोनम जंगपो भूटिया	DPO-पाक्योंग
33	सिक्किम	श्री कर्मा थेंदुप भूटिया	DPO/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी - मंगन
34	तमिलनाडु	श्री एस. रोबेश कुमार	सहायक निदेशक (पंचायतें) तिरुवल्लूर
35	तमिलनाडु	सुश्री जे. शोभना थांगम	ग्राम पंचायत अध्यक्ष, कोवलम
36	तमिलनाडु	श्री एस. राम शंकर	ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ब्रह्मदेशम
37	त्रिपुरा	सुश्री सुप्रिया दास दत्ता	सभापति, जिला अध्यक्ष, जिला परिषद
38	त्रिपुरा	डॉ. सिद्धार्थ शिव जायसवाल	जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर - धलाई
39	त्रिपुरा	श्री साजू वहीद ए.	जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर - दक्षिण त्रिपुरा
40	उत्तर प्रदेश	श्री गौरव चौधरी	अध्यक्ष, जिला परिषद मेरठ
41	उत्तर प्रदेश	सुश्री नुपुर गोयल	CDO, मेरठ
42	उत्तर प्रदेश	श्री प्रणव पांडे	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मऊ
43	उत्तर प्रदेश	सुश्री मोनिका यादव	अध्यक्ष जिला पंचायत, फरुखाबाद
44	उत्तर प्रदेश	श्री संतोष कुमार त्रिपाठी	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हाथरस
45	उत्तराखंड	डॉ. सुनील कुमार	अपर मुखिया अधिकारी - पौड़ी
46	उत्तराखंड	सुश्री मधु चौहान	अध्यक्ष जिला परिषद-देहरादून
47	उत्तराखंड	श्री भागवत पटनी	अपर मुखिया अधिकारी - चंपावत
48	झारखंड	सुश्री शारदा सिंह	अध्यक्ष जिला परिषद धनबाद
49	झारखंड	सुश्री शांति देवी	अध्यक्ष, जिला परिषद, गढ़वा
50	अंडमान और निकोबार द्वीप	श्री आशिष जोन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - उत्तर और मध्य अंडमान
51	अंडमान और निकोबार द्वीप	श्री सुब्रेटा बसु	जिला परिषद अध्यक्ष, उत्तर और मध्य अंडमान

अनुबंध -II

दिनांक 30/07/2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1332 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत अनुमोदित कंप्यूटरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जानकारी और भारतनेट परियोजना के तहत उपलब्ध इंटरनेट कनेक्शन स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत अनुमोदित कंप्यूटर	भारतनेट परियोजना के तहत सेवा सक्षम जीपी/टीएलबी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	81
2	आंध्र प्रदेश	1000	12,966
3	अरुणाचल प्रदेश	1200	1,117
4	असम	1000	1,634
5	बिहार	534	8,860
6	छत्तीसगढ़	600	9,759
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	0	14,559
9	हरियाणा	0	6,204
10	हिमाचल प्रदेश	334	415
11	जम्मू और कश्मीर	1318	1,113
12	झारखंड	240	4,646
13	कर्नाटका	0	6,251
14	केरल	0	1,130
15	लद्दाख	123	193
16	लक्षद्वीप	0	9
17	मध्य प्रदेश	0	18,105
18	महाराष्ट्र	0	24,597
19	मणिपुर	120	1,479
20	मेघालय	2854	696
21	मिजोरम	1182	529
22	नागालैंड	488	233
23	ओडिशा	50	7,099
24	पुडुचेरी	0	101
25	पंजाब	0	12,807
26	राजस्थान	1554	8,997
27	सिक्किम	235	54

28	तमिलनाडु	0	9,748
29	तेलंगाना	3624	10,913
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	41
31	त्रिपुरा	950	771
32	उत्तर प्रदेश	6290	47,316
33	उत्तराखंड	500	2,014
34	पश्चिम बंगाल	0	2,958
	कुल	24196	2,17,395
